

समुद्री खाद्य निर्यात 72,000 करोड़

नई दिल्ली, 22 अप्रैल. अमेरिकी बाजार में गिरावट के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ रुपये (8.28 अरब डॉलर) तक पहुंच गया.

इस वृद्धि का मुख्य कारण अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों में समुद्री खाद्य निर्यात के प्रयास में मिली महत्वपूर्ण सफलताएं हैं। समुद्री खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा) के ताजा आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष में समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात मात्रा के हिसाब से 19.32 लाख टन तक पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में खलल के बीच इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। निर्यातों को इस वृद्धि में



फ़ोजन झोंगा का प्रमुख योगदान रहा. वर्ष के दौरान इसके निर्यात ने 47,973.13 करोड़ रुपये (5.51 अरब अमेरिकी डॉलर) का योगदान दिया था, जो कुल निर्यात आय के दो-तिहाई से अधिक है. झोंगा की खेप की मात्रा में 4.6 प्रतिशत और मूल्य में 6.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वर्ष के

दक्षिण-पूर्व एशिया में भी विशेष विस्तार हुआ, जहां मूल्य और मात्रा में क्रमशः 36.1 प्रतिशत और 28.2 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई. जापान को निर्यात मूल्य में 6.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पश्चिम एशिया को निर्यात में वित्तीय वर्ष के अंत में क्षेत्र में व्याप्त अशांति के कारण 0.55 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गयी. कुल निर्यात मूल्य में लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा रहा.

दौरान भारत के समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात टिकना बना रहा और वहां के लिए निर्यात 2.32 अरब डॉलर रहा. इस दौरान हालांकि भारत के खिलाफ शुल्क बढ़ाये जाने के प्रभाव से अमेरिका को किया गया निर्यात मात्रा में एक साल पहले की तुलना में 19.8 प्रतिशत और मूल्य में 14.5 प्रतिशत घट गया. चीन, यूरोपीय संघ और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे वैकल्पिक बाजारों में मजबूत बढ़ोतरी से इस गिरावट को भरपाई हुई.

भारत में जमीन सौदों में 32 प्रतिशत उछाल

नई दिल्ली, 22 अप्रैल. भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में 2025 के दौरान जमीन अधिग्रहण में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है, जो इस उद्योग में डेवलपर्स के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, सालभर में 149 सौदों के जरिए करीब 3,093 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिसकी कुल वैल्यू 54,818 करोड़ रुपये रही. यह उछाल मजबूत मांग और आने वाले वर्षों में बढ़े निर्माण प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं का संकेत देता है. रिपोर्ट बताती है कि खरीदी गई जमीन पर अगले 2 से 5 साल में लगभग 229 मिलियन स्क्वायर फीट निर्माण संभव है. हालांकि, निवेश का बड़ा हिस्सा टियर-1 शहरों में केंद्रित रहा, जहां 89 प्रतिशत पूंजी लगी, जबकि जमीन का हिस्सा 52 प्रतिशत ही रहा.

एफडीआई निकासी अस्थायी: गवर्नर

अल्पकालिक उतार-चढ़ाव, मजबूत आर्थिक आधार कायम

मजबूत आर्थिक संकेतकों से भरोसा बरकरार



नई दिल्ली, 22 अप्रैल भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के दिनों में देखे जा रहे उतार-चढ़ाव, विशेषकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के बाहर जाने को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्थिति को लेकर भरोसा जताया है. आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि एफडीआई निकासी और बाजार में अस्थिरता जैसी घटनाएं अल्पकालिक हैं और इन्हें दीर्घकालिक आर्थिक कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं देखा जा चाहिए.

कारण पूंजी का आवागमन एक सामान्य प्रक्रिया है. भारत जैसे उभरते बाजारों में इस तरह के उतार-चढ़ाव स्वाभाविक हैं और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है. आरबीआई इन सभी गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाने के लिए तैयार है. हाल के महीनों में विदेशी निवेश में कुछ कमी देखी गई है, जिससे रुपये पर दबाव और शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है. देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताते हुए आरबीआई ने कई प्रमुख संकेतकों का उल्लेख किया. महंगाई दर नियंत्रण में बनी हुई है, चालू खाते का घाटा सीमित दायरे में है और विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त स्तर पर है. ये सभी कारक इस बात का संकेत देते हैं कि भारत बाहरी आर्थिक झटकों को सहने में सक्षम है. इसके साथ ही भारत की विकास दर भी वैश्विक स्तर पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बनी हुई है. सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और सुधारों की निरंतर प्रक्रिया ने देश को निवेश के लिए आकर्षक बनाए रखा है.

होर्मुज संकट से तेल आपूर्ति पर खतरा मंडराया



नई दिल्ली, 22 अप्रैल. होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर संकट में डाल दिया है, जिससे भारत और संकट जैसे बड़े तेल आयातक देशों की चिंता बढ़ गई है.

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह अहम समुद्री मार्ग लगभग ठप हो चुका है, जिसके चलते कच्चे तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार, संकट की शुरुआत में भारत और चीन ने समुद्र

में पहले से मौजूद रूसी और ईरानी तेल कार्गो का सहारा लिया था. ये वे जहाज थे जो ट्रांजिट में थे या समुद्र में ही स्टोरेज के रूप में खड़े थे, लेकिन अब यह 'बैकअप' तेजी से खत्म हो रहा है. पहले जहां समुद्र में लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल उपलब्ध था, वहीं अब यह घटकर 50 लाख बैरल से भी कम रह गया है. कुछ आकलनों में यह मात्रा मात्र 30 लाख बैरल तक बताई जा रही है. स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि जो भंडार पहले कई हफ्तों तक चल सकता था, वह अब केवल कुछ दिनों के लिए ही पर्याप्त रह गया है. भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, अपनी ऊर्जा जरूरतों के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को रखांकित करती है. मंत्रालय के अनुसार, वर्ष

चावल, चीनी, खाद्य तेलों में तेजी, गेहूं नरम

नई दिल्ली, 22 अप्रैल. घरेलू थोक जिस बाजारों में बुधवार को चावल का औसत भाव बढ़ गया. चावल के साथ चीन और खाद्य तेलों में भी तेजी देखी गयी. गेहूं में नरमी का रुख रहा जबकि दालों के दामों में घट-बढ़ रही। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 10 रुपये बढ़कर 3,843 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। गेहूं की नरमि सस्ता हुआ और 2,774 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. आटे की कीमत पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर ही रही दाल-दलहनों में उतार-चढ़ाव देखा गया। तुअर दाल तीन रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई। मूंग दाल की कीमत 22 रुपये और उड़द दाल की 17 रुपये बढ़ गयी। चना दाल 13 रुपये और मसूर दाल छह रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

लॉन्च हुआ एआई-संचालित 'एक्सपर्टबुक अल्ट्रा'

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल. आसूस ने बुधवार को भारत में अपने नये एआई-संचालित 'एक्सपर्टबुक लैपटॉप' 'एक्सपर्टबुक अल्ट्रा' को लॉन्च करने के साथ ही एक्सपर्टबुक पी-सीरीज पोर्टफोलियो का विस्तार किया.

कंपनी ने बताया कि एक्सपर्टबुक अल्ट्रा एक कोपायलट लैपटॉप है, जिसे विशेष रूप से वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों और व्यवसाय से जुड़े पेशेवरों को जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह लैपटॉप अल्ट्रा-लाइट डिजाइन, उन्नत एआई-आधारित परफॉर्मेंस, उच्च गुणवत्ता वाले डिस्प्ले, बेहतर ऑडियो, लंबी बैटरी लाइफ और एंटरप्राइज-ग्रेड सुरक्षा जैसे फीचर्स से लैस है. एक्सपर्टबुक अल्ट्रा का वजन लगभग 0.99 किलोग्राम से शुरू होता है और इसे एजो31 भी



मैग्नीशियम-एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनाया गया है, जो आमतौर पर एयरोस्पेस और फॉर्मूला-1 अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होती है. इसमें नैनो-सिरेमिक कोटिंग दी गयी है, जिसकी कठोरता 9 एच

बतायी गयी है. कंपनी के अनुसार, यह डिवाइस इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज-3 प्रोसेसर पर आधारित है, जिसमें शक्तिशाली जीपीयू और उन्नत एनपीयू का संयोजन किया गया है. इससे एआई-आधारित काम तेजी से किये जा सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी ने एक्सपर्टबुक पी सीरीज में एक्सपर्टबुक पी3 और एक्सपर्टबुक पी5 मॉडल भी पेश किये हैं, जिन्हें छोटे और मध्यम उद्यमों तथा पेशेवरों की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है.

इस अवसर पर आसूस के ग्लोबल को-सीईओ सैमसन हू ने कहा कि कंपनी भारत में एआई-आधारित कंप्यूटिंग के नये दौर का नेतृत्व करना चाहती है. एक्सपर्टबुक अल्ट्रा के जरिए से पेशेवरों को बेहतर काम का अनुभव देने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, इंटेल इंडिया के वरिष्ठ निदेशक पीपी सुनिल आचार्य ने कहा कि आसूस के साथ सह-इंजीनियरिंग के जरिए एसा लैपटॉप तैयार किया गया है जो उच्च प्रदर्शन, इन-बिल्ट एआई क्षमताओं और ऊर्जा दक्षता का संतुलन प्रदान करता है.

कपड़ा निर्यात 2.1% बढ़कर मजबूत

पहले के 1,35,427.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,39,349.6 करोड़ कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 1,02,399.7 करोड़



नई दिल्ली, 22 अप्रैल. देश के वस्त्र उद्योग ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक बाजारों में स्थिर प्रदर्शन करते हुए कुल निर्यात में वृद्धि दर्ज की है. कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, हस्तशिल्प सहित कुल वस्त्र निर्यात 3,16,334.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले

वित्त वर्ष 2024-25 के 3,09,859.3 करोड़ रुपये की तुलना में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. यह वृद्धि वैश्विक स्तर पर भारतीय वस्त्र उत्पादों की लगातार बनी हुई मांग और क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को रखांकित करती है. मंत्रालय के अनुसार, वर्ष

के दौरान रेडीमेड गार्मेंट्स ने निर्यात में सबसे बड़ा योगदान दिया. इस श्रेणी का निर्यात एक वर्ष पहले के 1,35,427.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,39,349.6 करोड़ रुपये हो गया. जो 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. यह संकेत देता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय परिधानों की मांग लगातार बनी हुई है. सूती धागे, कपड़े, निर्मित वस्त्र और हथकरघा उत्पादों के निर्यात में भी हल्की वृद्धि दर्ज की गई. इस खंड का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 1,02,399.7 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 1,02,002.8 करोड़ रुपये था.

टेक महिंद्रा को चौथी तिमाही में 1,354 करोड़ का शुद्ध मुनाफा

मुंबई, 22 अप्रैल. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी टेक महिंद्रा को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में समेकित आधार पर 1,354 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है जो सालाना आधार पर 16 प्रतिशत अधिक है.

कंपनी के निदेशक मंडल की बुधवार को हुई बैठक में वित्तीय परिणामों को मंजूरी प्रदान की गयी. इसके अनुसार, चौथी तिमाही में राजस्व 12.6 फीसदी बढ़कर 15,076 करोड़ रुपये पर

रहा. प्रति शेयर आय 15.24 रुपये रही. पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का राजस्व 56,815 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 4,811 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. इनमें एक साल पहले के मुकाबले क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

निदेशक मंडल ने 36 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की भी घोषणा की. इससे पहले नवंबर 2025 में कंपनी ने प्रति इक्विटी शेयर 15 रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था.

सोना-चांदी में जोरदार उछाल, कीमतें चढ़ीं 1700 रुपए बढ़ा सोना 5000 रुपए उछली चांदी

नई दिल्ली, 22 अप्रैल. देश के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया, जिससे निवेशकों और खरीदारों दोनों की नजरें बाजार पर टिक गई हैं. 24 कैरेट सोना करीब 1,700 रुपये बढ़कर 1,53,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया,



जबकि 22 कैरेट सोना भी बढ़त के साथ 1,40,000 रुपये के पार बना हुआ है. चांदी की कीमतों में इससे भी बड़ा उछाल देखने को मिला है. एक ही दिन में करीब 5,000 रुपये की तेजी के साथ चांदी 1,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. यह बढ़ोतरी करीब 2 प्रतिशत

से अधिक की मानी जा रही है. जो बाजार में मजबूत मांग और वैश्विक संकेतों का असर दिखाती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में बढ़त, डॉलर में उतार-चढ़ाव और निवेशकों का सुरक्षित विकल्प की ओर रुख करना इस तेजी के प्रमुख कारण हैं. इसके अलावा भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता भी सोने-चांदी की मांग को बढ़ा रही है. बड़े शहरों में भी कीमतों में समान रूझान देखा गया है, जहां सोने के दाम नए उच्च स्तर के करीब बने हुए हैं.

समाचार विशेष

भाजपा के लिए चुनौती बरकरार या बन रही नई जमीन?

चेन्नई. तमिलनाडु की राजनीति दशकों से द्रविड़ दलों-डीएमके और एडीएमके के इर्द-गिर्द घूमती रही है. क्षेत्रीय पहचान, भाषा और सांस्कृतिक मुद्दों के दम पर इन पार्टियों ने राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है. यही वजह है कि भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी तमिलनाडु के बावजूद मतदाताओं के दिलों तक नहीं पहुंच पाई है. 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एडीएमके के साथ गठबंधन कर 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल कर पाई. वोट शेयर भी 3 प्रतिशत से कम रहा. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली. भाजपा ने पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई के हाथों में पार्टी की प्रदेश इकाई की कमान सौंपी. पार्टी ने राज्य भर में अपनी पकड़

मजबूत करनी शुरू की. 2024 का चुनाव भाजपा ने किसी भी द्रविड़ दल के साथ नहीं लड़ा, बावजूद इसके उसको जितने वोट मिले उसने सबको चौंका दिया. पार्टी लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 24 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने दक्षिणी तमिलनाडु और राजधानी चेन्नई में बेहतरीन प्रदर्शन किया. दक्षिण तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भाजपा उम्मीदवार ने 35.6 फीसदी वोट हासिल किया, जबकि तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम सीट पर वोट प्रतिशत 30 फीसदी से ज्यादा रहा. कुल मिलाकर दक्षिण तमिलनाडु में भाजपा ने अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर करीब 23 फीसदी वोट हासिल किया, जबकि पश्चिमी तमिलनाडु में करीब 19 फीसदी और चेन्नई में करीब 17 फीसदी वोट पार्टी को मिले.

पहले चरण में बाहुबलियों और धनकुबेरों का बोलबाला

23 प्रतिशत दागी और 21 प्रतिशत करोड़पति, सामने आई रिपोर्ट

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच ने उम्मीदवारों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया है. इस विश्लेषण में 152 निर्वाचन क्षेत्रों के 1,475 उम्मीदवारों को शामिल किया गया. इस रिपोर्ट के परिणाम बताते हैं कि राजनीति में धनशक्ति और अपराधीकरण का प्रभाव काफी गहरा है. रिपोर्ट के अनुसार, 66 निर्वाचन क्षेत्रों को 'रेड अलर्ट' घोषित किया गया है क्योंकि वहां



तीन या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. पहले चरण के उम्मीदवारों में अपराधियों की संख्या उग्राने वाली है. कुल विश्लेषण किए गए उम्मीदवारों में से 345 (23 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले और 294 (20 प्रतिशत) पर गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है

कि 19 उम्मीदवारों पर हत्या और 105 पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं. इसके अलावा, 98 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं, जिनमें से 6 उम्मीदवारों पर दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप हैं. राजनीतिक दलों के बीच तुलना करें तो आपराधिक मामलों की सूचना देने में भाजपा सबसे आगे है. भाजपा - 152 में से 106 उम्मीदवारों (70 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले और 63 प्रतिशत पर गंभीर आरोप हैं. सीपीएम - 98 में से 43 उम्मीदवारों (44 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले और 37 प्रतिशत पर गंभीर आरोप हैं.

जाकिर हुसैन 133 करोड़ के साथ सबसे अमीर

पहले चरण में कुल 309 (21 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं और प्रति उम्मीदवार औसत संपत्ति 1.34 करोड़ रुपये है. संपत्ति के मामले में तृणभूल कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे संपन्न हैं, जिनके 72 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं और उनकी औसत संपत्ति 5.70 करोड़ रुपये है. भाजपा के 47 प्रतिशत और कांग्रेस के 33 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति की श्रेणी में आते हैं.

विशेष | तमिलनाडु चुनाव की सबसे अमीर उम्मीदवार लीमा रोज

छठवीं पास और 1000 करोड़ की मालकिन!

चेन्नई. तमिलनाडु की राजनीति में इस बार 'धनबल' की खूब चर्चा हो रही है. विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जब नामांकन भरे गए, तो एक नाम ने सबको चौंका दिया. लीमा रोज मार्टिन. लीमा रोज ने केवल इस चुनाव की सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, बल्कि उनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा अच्छे-अच्छों के पर्सों से छुड़ा दे. लीमा रोज देश के मशहूर 'लॉटरी किंग' सेंटियागो मार्टिन की पत्नी हैं. वे पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और एआईएडीएमके (अन्नाद्रमुक) के टिकट पर लालगुडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, लीमा रोज की कुल संपत्ति 1,049 करोड़ से ज्यादा है. उनकी दौलत का गणित कुछ इस तरह है- अचल संपत्ति (जमीन-



की संपत्ति मिला दी जाए, तो पूरे मार्टिन परिवार की नेटवर्थ 4,000 करोड़ के पार पहुंच जाती है. 6वीं पास और सादगी भरा जीवन-हजारों करोड़ की मालकिन होने के बावजूद लीमा रोज की शैक्षिक योग्यता सिर्फ कक्षा 6 है. वे अब तक राजनीति से दूर रहकर अपने

मकान - लगभग 909.94 करोड़. चल संपत्ति (कैश, ज्वेलरी आदि) - लगभग 139.62 करोड़. अगर उनके पति और बेटे की संपत्ति मिला दी जाए, तो पूरे मार्टिन परिवार की नेटवर्थ 4,000 करोड़ के पार पहुंच जाती है.

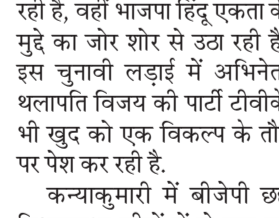
त्यों दिलचस्प है मुकाबला ?

इस बार तमिलनाडु का चुनाव पारंपरिक दलों की लड़ाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक दिलचस्प 'थ्री-वे' मुकाबले में बदल गया है. एक तरफ डीएमके गठबंधन है, जो सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश में जुटा है. दूसरी ओर एआईएडीएमके-पनडीए गठबंधन है, जो मजबूत चेहरों और रणनीतिक दम पर वापसी की तैयारी कर रहा है.

द्रविड़ नहीं कांग्रेस-बीजेपी की होती है जंग

चेन्नई. तमिलनाडु में राजनीति और चुनाव की बात आते ही जेहन में सबसे पहले डीएमके और एआईएडीएमके का नाम जेहन में आता है. लेकिन देश के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी में कहानी अलग चल रही है. कन्याकुमारी में द्रविड़ पार्टियों के बजाय कांग्रेस और बीजेपी के बीच असली जंग है.

पार्टनर तमिलनाडु मनीला कांग्रेस 'कमल' के निशान पर चुनाव लड़ रही है. दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से डीएमके ने जेहन में आता है. लेकिन देश के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी में कहानी अलग चल रही है. कन्याकुमारी में द्रविड़ पार्टियों के बजाय कांग्रेस और बीजेपी के बीच असली जंग है.



इस बार के चुनावी जंग में कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उठा रही है. वहीं भाजपा हिंदू एकता के मुद्दे का जोर शोर से उठा रही है. इस चुनावी लड़ाई में अभिनेता थलापति विजय को पार्टी टीवीके भी खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश कर रही है.

कारण हैं. इस जिले की आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी लगभग 47 फीसदी है. ईसाई पारंपरिक रूप से कांग्रेस के वोटर माने जाते रहे हैं. ऐसी स्थिति में यहां जब से बीजेपी सक्रिय हुई है तब से हिंदुओं को झुकाव इनकी तरफ हो गया है. कन्याकुमारी के इलाके में दक्षिणपंथी राजनीति की जड़ें 1972 से देखी जा रही हैं. यानी भाजपा की स्थापना से आठ साल पहले. जब आरएसएस के एआईएडीएमके ने अपना उम्मीदवार उतारा है. बाकी बची एक सीट पर पनडीए को एक और

मोदी और राहुल कर चुके हैं कन्याकुमारी में रेली

आगामी चुनावों में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी पारंपरिक ताकतों पर भरोसा कर रही हैं. साथ ही, दोनों को ही इस बात की भी उम्मीद है कि थलापति विजय की पार्टी टीवीके की वजह से वोटों में जो बंटवारा होगा, उसका लाभ उन्हें मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल को इस जिले में एक रोड शो किया, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने यहां 20 अप्रैल को चुनाव प्रचार किया. जमीनी स्तर पर, बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हिंदू परिवारों से संपर्क साध रहे हैं. 'वादे पूरे न कर पाने' और सत्ता-विरोधी लहर के मुद्दों पर कांग्रेस-डीएमके गठबंधन को निशाना बना रहे हैं.